मार्च 2025
वर्ष 39 संख्या 3
मूल्य 5 रुपये

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

प्रतिरोध का स्वर

हैदराबाद : कांग्रेस सरकार द्वारा चुनावी वायदे पूरा न करने के खिलाफ रैली

सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी ने तेलंगाना में कांग्रेस की रेवंथ रेड्डी सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए चुनावी वायदों को सत्ता में आने के 15 माह बाद भी लागू न करने के विरोध में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के नेतृत्व में 20 फरवरी 2025 को हैदराबाद में 15 महीने की कांग्रेस की रेवंथ रेड्डी सरकार द्वारा दी गई 6 गारंटी और लोकतांत्रिक शासन की 7 वीं गारंटी को लागू करने की मांग को लेकर हजारों लोगों ने विशाल प्रदर्शन कर धरना दिया। प्रदर्शन में 4 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया। सुंदरैया विज्ञान केंद्र से शुरू हुई रैली इंदिरा पार्क में एक विशाल धरने में बदल गई। विरोध प्रदर्शन को सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी के तेलंगाना राज्य प्रवक्ता जेवी चलपति राव, केंद्रीय समिति के सदस्य कामरेड सादिनेनी वेंकटेश्वर राव, पार्टी नेता अनुरी मधु, के. गोवर्धन, एआईकेएमएस के प्रदेश अध्यक्ष वी. कोटेश्वर राव, प्रदेश महासचिव मंडला वेकन्ना, पीओ डब्ल्यू के राष्ट्रीय नेता गाड़े, झांसी, वी संध्या, इफ्टू के राष्ट्रीय महासचिव टी. श्रीनिवास, प्रदेश महासचिव एम. श्रीनिवास, पीडीएसयू के राष्ट्रीय नेता पीएम महेश ने संबोधित किया।

सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी के नेताओं ने कहा कि रेवंथ सरकार ने चुनाव के समय जो 6 गारंटी दी थी, उन्हें अभी तक लागू न करके उसने जनता से वादाखिलाफी की है। इसलिए उन्हें तुरंत लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि लाखों लोग घरों और राशन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, जबकि रेवंथ सरकार पिछले 15 महीनों से सत्ता में है। जनता से किए गए वायदों को पूरा करने में वह पूरी तरह विफल रही है। वक्ताओं ने मांग की कि 'रायथु भरोसा बीमा' योजना के तहत किसानों और खेतिहर मजदूरों को दिए जाने वाले रु. 12000 का वायदा तुरंत लागू किया जाए। धरने के दौरान अरुणोदय ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

पार्टी नेताओं ने कहा कि लंबित फीस प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति जारी की जाए तथा बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए तेजी से कदम उठाए जाएं। जनता से किए गए वायदों को लागू न करने के कारण सभी वर्गों के लोग रेवंथ सरकार से बेहद असंतुष्ट हैं। पार्टी नेताओं ने सरकार से लोगों से किए गए वायदों को लागू करने के लिए सार्वजनिक रूप से एक विशिष्ट कार्य योजना जारी करने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि लोक

(शेष पृष्ठ 6 पर)

20 फरवरी 2025 को हैदराबाद में हुई रैली व सभा। ऊपर सभा का एक भाग तथा नीचे रैली का एक दृश्य

केन्द्रीय बजट 2025–'26

गहराता आर्थिक संकट, सामाजिक क्षेत्रों पर घटता खर्च व कारपोरेट की सेवा

केंद्र सरकार ने वर्ष 2025–'26 के लिए बजट पेश किया है, जो देश के लोगों के समक्ष बढ़ती समस्याओं के प्रति पूरी तरह असंवेदनशीलता और आर्थिक क्षितिज पर बढ़ती निराशा के बादलों की पूरी तरह उपेक्षा दर्शाता है। यह कॉरपोरेट की सेवा और जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने के लिए समर्पित बजट है। सरकार द्वारा इसे छुपाने के प्रयासों के बावजूद बजट गहराते आर्थिक संकट को नहीं छिपा सका है।

1 फरवरी को बजट पेश होने से एक दिन पहले, केंद्र सरकार ने संसद में 2024–25 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण ने न केवल आर्थिक विकास की दर में गिरावट को स्वीकार किया, बल्कि यह भी स्वीकार किया कि विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों के वेतन में भी चिंताजनक रूप से ठहराव या गिरावट आई है। पिछले छह वर्षों यानी 2017–18 से 2023–24 तक के आंकड़ों के अनुसार, कृषि में रोजगार का हिस्सा 2 प्रतिशत बढ़ा है यानी 44.1 प्रतिशत से 46.1 प्रतिशत हो गया है। दूसरी ओर, वेतनभोगी नौकरियों में श्रमिकों की हिस्सेदारी इसी अवधि में 22.8 प्रतिशत से घटकर 21.7 प्रतिशत हो गई है। इससे पहले सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में श्रमिकों के वेतन में गिरावट को स्वीकार किया था और शहरी पुरुष श्रमिकों को छोड़कर पुरुष और महिला दोनों कार्यबल के वेतन में गिरावट आई है तथा शहरी पुम्ष श्रमिकों के मामले में भी वृद्धि नाममात्र रही है। वास्तव में, वेतनभोगी पुरुष श्रमिकों का मासिक वेतन जो वैसे ही बहुत कम है इसमें 6.4 प्रतिशत की और गिरावट आई है जबकि वेतनभोगी महिला श्रमिकों के मासिक वेतन में इस अवधि में 12.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। दूसरी ओर, कंपनियों का मुनाफा पिछले साल पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक था। कर्मचारियों के खर्च में और वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कम हुई है। जहां वित्तीय वर्ष 2024 में कारपोरेट के मुनाफों में 22.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहीं उक्त वर्ष में कारपोरेट द्वारा रोजगार मात्र 1.5 पंतिशत बढ़ा है। साथ ही कारपोरेट द्वारा कर्मचारियों पर खर्च में वृद्धि दर पिछले साल के मुकाबले घटी है।

सरकार स्वरोजगार श्रेणी में अधिक रोजगार सृजित करने के लिए अपनी पीठ थपथपाती रही है। लेकिन सर्वेक्षण के अनुसार इन स्वरोजगार (या स्वरोजगार के लिए मजबूर) की औसत आय घटी है। पुरुष श्रमिकों के मामले में यह 9 प्रतिशत घटी है यानी 2017–18 में प्रति माह 9,454 रुपये से घटकर 2023–24 में प्रति माह 8,591 रुपये हो गई। महिला स्वरोजगार श्रमिकों की कमाई में और भी तेजी से गिरावट आई है यानी इसी अवधि में 4,348 रुपये से घटकर 2,950 रुपये हो गई अर्थात 32 प्रतिशत की गिरावट आई है।

भारतीय शासक वर्ग ने एफडीआई संचालित निर्यात आधारित विकास मॉडल को अपनाया है। लेकिन वैश्विक एफडीआई में भारतीय हिस्सेदारी केवल 2.5 प्रतिशत (1 ट्रिलियन डालर) है। सर्वेक्षण में विदेशी व्यापार में आर्थिक प्रतिकूलताओं का उल्लेख किया गया है, जो वास्तव में अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों में बढ़ते संरक्षणवाद के कारण है। ट्रम्प के नेतृत्व में टैरिफ बढ़ाने के अमेरिकी प्रयास का मूल उद्देश्य भारत सहित अन्य देशों को महंगे अमेरिकी सामान खरीदने के लिए मजबूर करके अपने व्यापार असंतुलन को ठीक करना है, यानी भारतीय उपभोक्ताओं पर महंगा अमेरिकी सामान थोपना है।

ऐसी स्थिति में यह उम्मीद की जा रही थी कि आरएसएस–भाजपा सरकार बजट में इन मुद्दों को संबोधित करेगी– यानी प्रभावी घरेलू मांग बढ़ाने का मुद्दा, गहराते कृषि संकट को दूर करना, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी में कमी और बढ़ती बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों सहित आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के मुद्दों को संबोधित करेगी। लेकिन मोदी सरकार ने लोगों की बिगड़ती परिस्थितियों के प्रति पूरी तरह असंवेदनशीलता दिखाई है और लोगों और देश के हितों को सबसे आगे रखने के प्रति पूरी अनिच्छा दिखाई है और खुद को केवल अपने कॉरपोरेट–विदेशी और घरेलू– लाभार्थियों को खुश करने तक ही सीमित रखा है।

घरेलू मांग बढ़ाने के सवाल पर, इस मुद्दे के महत्व को स्वीकार करने के बावजूद आरएसएस–भाजपा सरकार उपाय करने में सबसे ज्यादा अनिच्छुक रही है। इस संबंध में एकमात्र उपाय सालाना 12 लाख तक की आय पर आयकर से छूट (रिबेट) देना प्रतीत होता है। लेकिन इस उपाय से लगभग 1 लाख करोड़ रुपये (लगभग 11.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का लाभ पहुंचाने का दावा किया गया है, जो ठहरावग्रस्त घरेलू मांग के प्रश्न का समाधान करने के लिए बहुत छोटी राशि

(शेष पृष्ठ 5 पर)

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आह्वान

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के लिए संघर्ष- हमारा अधिकार!

महिलाओं के खिलाफ हिंसा बंद करो!

महिला राजनीतिक कैदियों को रिहा करो! UAPA को निरस्त करो! संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल करो!

दुनिया भर में लोकतांत्रिक संघर्ष में महिलाओं के साथ एकजुटता!

फिलिस्तीन की महिलाओं को सलाम!

8 मार्च 2025, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत में महिलाओं को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे समाज में तथा औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था दोनों में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में कम है। यह तब है जब महिलाएं घर के सभी कामों का अधिकतम बोझ उठाती हैं और हर क्षेत्र में नौकरियों के लिए योग्य भी होती हैं। एक अर्ध सामंती संस्कृति प्रचलित है और इस स्थिति को उचित ठहराती है। इसके प्रभाव में, घरेलू क्षेत्र और समाज दोनों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा जारी है।

इसके अलावा, 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है जो मनुवाद को बढ़ावा देती है। इस प्रकार सबसे पिछड़ी पितृसत्तात्मक प्रथाओं को वैधता दी जाती है। दलितों और अल्पसंख्यकों की महिलाओं पर विशेष रूप से हमले किए जाते हैं। अंतरधार्मिक और अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों पर हिंसक हमले और हत्याएं, अपमानजनक 'ऑनर किलिंग' लगभग आम बात हो गई है। दलित महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा सहित हिंसा बढ़ रही है।

इस परिवेश में, महिलाओं के अधिकारों पर भी सर्वत्र पितृसत्तात्मक हमला बढ़ गया है। महिलाओं और समाज के शक्तिशाली आंदोलनों के बावजूद महिलाओं पर यौन हिंसा में वृद्धि जारी है। यह तब और भी अधिक है जब आरोपी राज्य सत्ता में बैठे लोग हों। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और हिंसा बड़े पैमाने पर होती है, यहां तक कि अदालतों के परिसरों में भी कानूनों का उल्लंघन होता है और न्याय से वंचित किया जाता है। यही सच है चाहे महिलाएँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित पहलवान हों, कठुआ की एक बच्ची हो या हाथरस की दलित लड़की हो या मणिपुर की आदिवासी महिलाएँ हो या हाल ही में बंगाल की स्नातकोत्तर डॉक्टर। यौन हिंसा के आरोपियों के उच्च और शक्तिशाली होने पर राज्य द्वारा की जाने वाली ये लीपा पोती केरल में सिने उद्योग में महिलाओं पर यौन हिंसा के संबंध में गठित आयोग की रिपोर्ट में भी सामने आई, जिसे राज्य सरकार द्वारा दबा दिया गया था।

जबकि सरकारें और खास तौर पर केंद्र सरकार महिलाओं को देवी मानती हैं और नारी शक्ति की बात करती हैं और 'बहनों' के लिए अपनी चिंता जताती हैं, महिलाओं के खिलाफ संरचनात्मक हिंसा हमेशा चरम पर है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवसायीकरण की राह पर हैं। दरिद्रता इतनी व्यापक है कि भुखमरी से बचने के लिए केंद्र को भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त देना पड़ रहा है। गरीबी का असर महिलाओं पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वे अपने परिवार को 'थोड़ा ज्यादा' देने के लिए खुद को वंचित रखती हैं। अधिकांश जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं।

औपचारिक नौकरियों में महिलाओं की संख्या घट रही है, ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में महिलाओं की मजदूरी 2013–14 और 2023–24 के बीच यानी पिछले दस सालों में घटी है। सफाई कर्मचारियों से लेकर शिक्षकों, प्रोफेसरों, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों तक में ठेकेदारी और अस्थायी काम का चलन है, और इसमें भी महिलाओं को समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है, जबकि ईएसआई अधिकार लागू न होने का मतलब है कि महिलाएं मातृत्व लाभ से वंचित हैं। पीएफ का वैधानिक अधिकार, जो महिलाओं को सशक्त बनाता है, छीना जा रहा है, न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं की जाती है, और काम के घंटे नियमित रूप से कानूनी सीमाओं से अधिक होते हैं। यह केंद्रीय सरकार के श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के लागू होने से पहले ही है, जो वैसे भी कामकाजी महिलाओं सहित श्रमिकों के कई कानूनी अधिकारों को खत्म कर देगा। मनरेगा के लिए बजट वास्तविक रूप से कम हो रहा है – यह ग्रामीण महिलाओं को 100 दिनों की मामूली अवधि ही सही के लिए मजदूरी देता है और वह भी न्यूनतम मजदूरी पर नहीं। नियमित कार्यबल में महिलाओं की पूरी श्रेणियों को सहायक, स्वैच्छिक आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कानूनी रूप से लागू मजदूरी के स्थान पर बहुत कम भुगतान किया जाता है। पितृसत्तात्मक सांस्कृतिक प्रथाओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है जबकि गीतों के द्वारा और हास्य के नाम पर महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है तथा वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

महिलाओं को उनकी कानूनी मजदूरी से वंचित किया जाता है, उन्हें लाडली बहन, लड़की बहन, सुभद्रा, सम्मान मैया और महिला समर्थन के रूप में पुकारा जाता है और महीने में एक या दो हजार की मदद दी जाती है। यह एक चतुराई भरा तरीका है जो दिखाता है कि महिलाएँ कितनी मुश्किलों में हैं क्योंकि ज्यादातर घरों में दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती। खेत मजदूरों की मजदूरी लागू नहीं की जाती और लैंगिक असमानता होती है। महिलाओं के रोजगार विवरण में, स्वरोजगार में लगी महिलाएँ चार्ट में सबसे ऊपर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सब्जी बेचने वाली, ट्रेन में टोपी और मोजे बेचने वाली और मूंगफली बेचने वाली सभी इसी श्रेणी में आती हैं! सशक्तिकरण के नाम पर स्व–सहायता और माइक्रोफाइनेंस योजनाओं के जरिए मुनाफे की लूट के लिए महिलाओं को फँसाया जा रहा है।

जबकि काम के घंटों पर बने कानून लागू नहीं होते हैं, बड़े पूंजीपतियों द्वारा 90 घंटे, 7 दिन के सप्ताह और इस तरह के संयोजनों के लिए लगातार दबाव डाला जा रहा है। केंद्र सरकार के लेबर कोड इन संभावनाओं के लिए दरवाजे खोल देंगे। इसका निश्चित प्रभाव कामकाजी महिलाओं पर बोझ को बहुत बढ़ाना होगा और निश्चित रूप से उन्हें औपचारिक रोजगार से पूरी तरह से बाहर करना होगा, साथ ही उनके स्वास्थ्य को और भी खराब करना होगा। ज्यादातर महिलाओं को लगातार घरेलू कामों के साथ सातों दिन काम करना होता है। 12 घंटे औपचारिक काम, आने जाने में लगने वाले घंटे और हर रोज का घरेलू काम ही असलियत होगी।

पसंद की आजादी पर हमले जारी हैं। महिलाओं के लिए हानिकारक प्रथाओं को बदलने के नाम पर उत्तराखंड में एक समान नागरिक संहिता पारित की गई है। अभी इसे सिर्फ एक बिंदु पर लागू किया जा रहा है, सभी 'लिव इन' को पंजीकृत करना। रिकॉर्ड का इस्तेमाल निश्चित रूप से नैतिक पुलिसिंग के लिए किया जाएगा और महिलाओं और उनके साथियों को निशाना बनाने में मदद की जाएगी। 'लव जिहाद' से लड़ने के नाम पर, 12 भाजपा शासित राज्यों ने इसी उद्देश्य से कानून बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। लेकिन भरण–पोषण के लिए कानून, वैवाहिक घर में रहने के अधिकार को लागू करने के लिए कानून, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून, सभी का क्रियान्वयन सुस्ती से किया जाता है। विशेष विवाह अधिनियम के तहत अंतर–धार्मिक और अंतरजातीय जोड़ों के आवेदन आवेदकों का पता लगाने और अक्सर उन्हें मार डालने का एक तरीका बन गए हैं, जिसमें राज्य सरकारें और पुलिस सुविधाकर्ता नहीं तो मूकदर्शक ही बनी रहती हैं।

संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगाया जा रहा है। पुलिस ने 2024 में राजधानी में 8 मार्च को संयुक्त महिला संगठनों की बैठक की अनुमति देने से इनकार कर दिया और इसमें भाग लेने आई सभी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। यौन हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन करने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित महिला पहलवानों को गिरफ्तार किया गया और उनकी पिटाई की गई। महिलाओं और छात्रों पर CAA विरोधी प्रदर्शनों के लिए UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें जमानत देने से इनकार किया जा रहा है। विस्थापन का विरोध करने के लिए कई आम आदिवासी महिलाओं को UAPA के तहत जेलों में ठूंस दिया गया है। महिला श्रमिकों को नौकरी और वेतन के संघर्षों में भाग लेने के लिए दमन का सामना करना पड़ा है।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जनविरोधी नीतियों को लागू कर रही हैं और भारत की जघ्मीन को बड़ी कंपनियों, मुख्य रूप से विदेशी कंपनियों को सौंप रही हैं। आदिवासियों को जंगलों से जबरन बेदखल किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में हजारों महिलाएँ विस्थापित हैं। कृषि भूमि को कंपनियों को सौंपने की कोशिश की जा रही है। जहां इस तरह से जमीन सौंपी जा रही है लेकिन सरकारें न तो जमीन सीलिंग को लागू कर रही हैं और न ही संयुक्त नाम के पट्टों के साथ भूमि पुनर्वितरण कर रही हैं और इस तरह भारत में भूमिहीन महिलाओं की बड़ी संख्या को सरकारें जमीन देने से मना कर रही हैं।

निरंतर, निरंतर व्यापक संघर्ष ही रास्ता है!

इस 8 मार्च को, हम भारत की महिलाओं से आह्वान करते हैं:

आइये, पितृसत्ता के खिलाफ संघर्ष को तेज करें। आइये, समाज और अर्थव्यवस्था में समान दर्जे के लिए संघर्ष करें।

आइये, हम सब मिलकर वेतन वाली नौकरी, भूमि, समान वेतन, स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार, शिक्षा, आश्रय और समाज, कार्यस्थल, घर में सुरक्षा के लिए लामबंद हों !

आइए, हम मांग करें कि हमारी जनविरोधी सरकारों द्वारा जबरन विस्थापन तथा हमारे देश की भूमि और कृषि को लुटेरों, मुख्यतः बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपने पर रोक लगाई जाए।

आइए, हम कार्यस्थल पर सुरक्षा की मांग करें। यौन हिंसा के सभी मामलों में निष्पक्ष, त्वरित जांच और त्वरित, न्यायपूर्ण सुनवाई के माध्यम से सजघ की गारंटी के लिए लडधें।

आइये, हम अपने चुनने के अधिकार की रक्षा और उसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करें।

8 मार्च को हम भारत और पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक संघर्षों में शामिल महिलाओं को सलाम करते हैं। हम अन्यायपूर्ण, साम्राज्यवाद प्रायोजित युद्धों में विस्थापित और वंचित महिलाओं को सलाम करते हैं। *हम जायोनीवादियों और पश्चिमी साम्राज्यवादियों से अपने देश की रक्षा के लिए संघर्ष में लगी फिलिस्तीन की महिलाओं को विशेष सलाम करते हैं।*

अखिल भारतीय कोआर्डिनेशन

प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वूमेन (POW)

प्रगतिशील महिला संगठन (PMS)

स्त्री जागृति मंच (पंजाब) (IJM)

दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणामों पर

पिछले 27 सालों में लगातार 6 विधानसभा चुनाव हारने के बाद 8 फरवरी को घोषित दिल्ली विधानसभा के नतीजों में आरएसएस–भाजपा ने बहुमत प्राप्त कर लिया। सीटों के मामले में जीत (70 में से 48 सीटें) वोटों के मामले में पार्टियों के बीच फासले से कहीं अधिक व्यापक थी इसका कारण है 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' निर्वाचन प्रणाली जिसके अनुसार सइसे अधिक वोट पाने वाला विजयी घोषित होता है तथा सीटों का बंटवारा पेाप्त वोटों के अनुपात में नहीं होता। बहरहाल चुनाव में भाजपा तथा आप पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिली। आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस लगातार तीसरी बार खाली हाथ रही। आप ने पिछले दो चुनावों में – 2015 में 70 में से 67 और 2020 में 70 में से 62 सीटें हासिल करके शानदार जीत हासिल की थी। 2013 में पहली बार 28 सीटें हासिल करके और उसके बाद कांग्रेस की मदद से आप पार्टी ने सत्ता हासिल की थी।

वोटों के मामले में आप ने पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 10 प्रतिशत वोट शेयर खो दिया है। इस बार उसे 43.57 प्रतिशत वोट मिले हैं, जबकि 2020 के पहले पिछले चुनाव में उसे 53.57 प्रतिशत वोट मिले थे। दूसरी ओर भाजपा को 45.55 वोट और उसके सहयोगी जदयू और एलजेपीरावि के वोटों सहित लगभग 47.1 प्रतिशत वोट मिले। कांग्रेस को इन चुनाव में 6.34 प्रतिशत वोट मिले, जो पिछले चुनावों यानी 2020 की तुलना में लगभग 2.01 प्रतिशत अधिक है।

आप पार्टी की हार का सबसे महत्वपूर्ण कारण मध्यम वर्ग के मतदाताओं के एक हिस्से का उससे दूर हो जाना है। पिछले तीन चुनाव में आप को मध्यम वर्ग के एक ऐसे हिस्से से वोट मिलते थे, जो संसदीय चुनाव में आरएसएस–भाजपा को वोट देता था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप को वोट देते थे। 2020 के चुनाव अभियान के दौरान आप पार्टी के नेताओं द्वारा गढ़ा गया नारा 'केंद्र के लिए मोदी और दिल्ली के लिए केजरीवाल' विशेष रूप से इसी वर्ग को लक्षित करता था। मध्यम वर्ग के इस वर्ग का मोह भंग, जिसने तथाकथित मोदी लहर के चरम पर भी आरएसएस–भाजपा को वोट नहीं दिया था, कई कारणों से हुआ है। इनमें सबसे बड़ा कारण राजधानी में नागरिक सुविधाओं की स्थितियों का बिगड़ना, गंदगी के बढ़ते ढ़ेर, वायु प्रदूषण, गंदा पानी, खस्ताहाल सड़कें और अन्य नागरिक सुविधाओं की बदहाल स्थिति है। आरएसएस– भाजपा सरकार द्वारा 12 लाख रुपए तक की आय वालों को आयकर में छूट देने से भी उन्हें इस मोहभंग को मजबूत करने में मदद मिली।

दूसरी ओर भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा के रूप में आप पार्टी की चमक फीकी पड़ गई है। इलाकों में शराब की दुकानें खुलने से कम से कम कुछ तबकों में आप के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को बल मिला। इसके अलावा तथाकथित भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जो इस मिलीभगत वाले भ्रष्टाचार के आधार यानी बड़ी पूंजी (कॉरपोरेट) के आधार को नहीं छूते हैं और इसलिए शासक वर्ग की राजनीति के दायरे में रहते हैं, उनका जीवन काल लंबा नहीं होता है। जैसा कि जयप्रकाश नारायण और वीपी सिंह नेतृत्वाधीन आंदोलनों ने भ्रष्टाचार की समाप्ति पर कोई प्रभाव नहीं डाला और वे अन्य पहलुओं के लिए जाने जाते हैं। जैसे जेपी नारायण के मामले में आपातकाल को पराजित करना और वीपी सिंह सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए मंडल आयोग को लागू करना रहा है, जबकि भ्रष्टाचार पानी की तरह वर्तमान शासक वर्गों के शासन में नए रास्ते खोजता रहा है।

आप पार्टी को गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के बड़े हिस्से का समर्थन मिला। सत्ता में आने के पहले कार्यकाल में इसने घरेलू उपयोग के लिए 200 यूनिट तक की बिजली और पानी के बिल माफ किए थे। बसों में महिलाओं की यात्रा मुफ्त की और पुलिस द्वारा खासकर ऑटो चालकों और रेहड़ी–पटरी वालों को परेशान करने के मामलों में काफी कमी हुई थी। इन राहतों ने आप पार्टी को गरीब तबकों के लोगों के बीच आधार प्रदान किया था, जिनमें से अधिकांश ने इन चुनावों के दौरान भी आपका साथ नहीं छोड़ा। स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित अन्य उपाय जिन्हें आप पार्टी दिल्ली मॉडल के रूप में प्रचारित करती है, हालांकि वे विश्वसनीय वैकल्पिक मॉडल नहीं हैं, इन वर्गों द्वारा सकारात्मक रूप से देखे जाते हैं।

जहां आरएसएस–भाजपा की केंद्र सरकार ने दिल्ली में आप सरकार के कामकाज में बाधा डालने के लिए सभी उपाय किए और दिल्ली सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम 2023 के संशोधन के बाद दिल्ली में मुख्य रूप से उपराज्यपाल का ही शासन रहा है। दूसरी ओर आप पार्टी ने खुद को केंद्र पर दोष देने तक ही सीमित रखा, लेकिन अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया। इनमें से सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप से मजदूर वर्ग से संबंधित है, जहां आप सरकार ने न्यूनतम मजदूरी या सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए कुछ नहीं किया। इसके अलावा आप सरकार ने आरएसएस–भाजपा सरकार द्वारा लाए गए चार श्रम संहिताओं या एनईपी 2020 का विरोध नहीं किया। आप नेताओं ने सीएए–एनआरसी–एनपीआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों पर अलग–अलग बातें कहीं। यही नहीं दिल्ली की सीमाओं पर हुए ऐतिहासिक किसान आंदोलन पर भी चुप रहे।

आप पार्टी की हार शासक वर्ग के सुधारवाद की सीमाओं को भी दर्शाती है। मेहनतकश जनता के बीच आप के बारे में फैलाया गया भ्रम खत्म हो रहा है, लेकिन आप और शासक वर्ग के अन्य विकल्पों के पतन के पिछले असली कारण यह हैं कि शासक वर्ग का बड़ा हिस्सा निरंकुश शासन की ओर बढ़ रहा है। इसलिए उनमें से बड़ा हिस्सा आरएसएस–भाजपा का समर्थन कर रहा है।

कांग्रेस और आप पार्टी दोनों ही आरएसएस–भाजपा की तानाशाही का विरोध करने की बात तो करते हैं, लेकिन उनका ध्यान आरएसएस–भाजपा को हराने की बजाय अपनी ताकत बढ़ाने पर ज्यादा है। 2024 के आम चुनाव से पहले शासक वर्गों के विपक्षी दलों ने आरएसएस–भाजपा के खिलाफ हाथ मिला लिया था और इसने विभिन्न वर्गों के लोगों के बढ़ते गुस्से के बल पर आरएसएस–भाजपा को अल्पमत में ला दिया था। आरएसएस–भाजपा को एनडीए सहयोगियों के साथ सरकार बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन संसदीय चुनाव के बाद शासक वर्गों के विपक्षी दल यह सोच कर बिखर गए कि खतरा टल गया है। वर्तमान दिल्ली चुनाव को ही लें, तो आप और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़े। इसका नतीजा यह हुआ कि कम से कम 14 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। 12 सीटें ऐसी हैं, जहां कांग्रेस को भाजपा उम्मीदवारों की आप उम्मीदवारों पर जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले। एक ऐसी सीट जहां आप को भाजपा उम्मीदवार की कांग्रेस उम्मीदवार पर जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले और एक ऐसी सीट, जहां आप, एआईएमआईएम और कांग्रेस के बीच तीन तरफा बंटवारा हुआ जिसके कारण भाजपा की जीत हुई। आप की हार पर अपनी खुशी जाहिर कर कांग्रेस के नेता अदूरदर्शिता का परिचय दे रहे हैं।

मुख्य कारण यह है कि शासक वर्ग की पार्टियां फासीवादी आरएसएस–भाजपा से भिड़ना नहीं चाहती हैं। उनकी रणनीति आरएसएस–भाजपा के आधार को जीतने के लिए ज्यादा दक्षिणपंथी रुख अपनाना है, जिससे पूरी शासक वर्ग की राजनीति और ज्यादा दक्षिणपंथी हो रही है। आप द्वारा नरम हिंदुत्व को अपनाना एक घिसी–पिटी रणनीति है। जब इसका शुद्ध रूप उपलब्ध है तो लोग नरम संस्करण को क्यों पसंद करें! यह सोचना कि नरम हिंदुत्व का दिखावा लोगों को दूसरे मुद्दों पर वोट करने की ओर ले जाएगा, कुछ समय के लिए तो काम कर सकता है, लेकिन लंबे समय में यह आत्मघाती है। आप पार्टी कांग्रेस से यह सबक सीख सकती थी, लेकिन उन्हें इतना भरोसा था कि उनके दिल्ली के किले को भेदा नहीं जा सकता, कि वह कुछ भी सीखने के लिए तैयार नहीं थे।

एआईएमआईएम ने ओखला और मुस्तफाबाद दो क्षेत्रों से उम्मीदवार उतारे थे, दोनों ही जगहों पर मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी आबादी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े मामलों में जेल में बंद एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को अच्छे वोट मिले, जिसका मुख्य कारण दिल्ली में शासक वर्ग की मुख्य पार्टियों – आप और कांग्रेस द्वारा 2020 में सीएए–एनआरसी–एनपीआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर मुसलमानों पर किए गए कठोर दमन के मुद्दों को नहीं उठाना था।

संसदीय वामपंथी दलों सीपीएम, सीपीआई और सीपीआई (एमएल) लिबरेशन ने 9 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा। सीपीआई ने 5, सीपीएम और लिबरेशन ने दो–दो उम्मीदवार उतारे। इन पार्टियों ने पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन किया था।

इन चुनावों ने स्पष्ट रूप से वर्ग विभाजन को प्रदर्शित किया है। गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के बड़े हिस्से ने आरएसएस– भाजपा से काफी हद तक दूरी बनाए रखी है। सिवाय एक वर्ग के जो उनके सांप्रदायिक विभाजनकारी खेल से प्रभावित है। आरएसएस– भाजपा के प्रति मेहनतकश लोगों के रवैये ने इस वर्ग के संघर्ष को खड़ा करना जरूरी बना दिया है। ताकि वह निराशा और वैकल्पिक मार्ग की कमी के कारण आरएसएस के प्रचार में ना फंस जाएं।

2024 में संसदीय चुनाव में कुछ झटका लगने के बाद आरएसएस–भाजपा ने हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और अब वह दिल्ली में जीत हासिल कर चुके हैं। वह अपनी चुनावी जीत का इस्तेमाल अपने फासीवादी अभियान को और तेज करने की कोशिश में करेंगे। इससे जनांदोलनों और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा बढ़ जाता है। अब जबकि आरएसएस–भाजपा लगभग पूरे हिंदी भाषी क्षेत्रों और पश्चिमी भारत पर राज कर रही है, तो आरएसएस–भाजपा के फासीवादी अभियान का खतरा और बढ़ गया है।

यह चुनाव एक बार फिर फासीवादी ताकतों का सामना करने में शासक वर्ग के विपक्षी दलों की ईमानदारी की कमी और अदूरदर्शिता को दर्शाते हैं। यह एक बार फिर आरएसएस–भाजपा के फासीवादी अभियान का सामना करने, उसे अलग–थलग करने और उसे हराने के लिए विभिन्न वर्गों और जन आंदोलनों के संघर्षों के निर्माण के महत्व को उजागर करता है।

(सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी द्वारा 9 फरवरी 2025 को जारी बयान का अनुवाद)

दिल्ली 4 मार्च। ओखला में मजदूरों की मांगों पर प्रदर्शन करते इफ्टु से सम्बंधित मजदूर

हाल की अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय घटनाओं पर – 3

(सीपीआई (एम-एल) न्यू डेमोक्रेसी की केंद्रीय समिति ने दिसम्बर 2024 के मध्य में अपनी बैठक में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं पर एक वक्तव्य को मंजूरी दी। इस वक्तव्य का तीसरा अंश हम प्रतिरोध का स्वर के इस अंक में प्रकाशित कर रहे हैं। - संपादक)

पड़ोसी देशों के घटनाक्रम

बांग्लादेश :

पिछले कुछ महीनों में हमारे पड़ोसी देशों में गंभीर घटनाएं हुई हैं। जून के अंत से एक गंभीर छात्र आंदोलन ने बांग्लादेश के अलग देश बनाने के लिए लड़ने वालों के वंशजों के लिए 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने पर शेख हसीना सरकार को चुनौती दी। इस व्यापक आंदोलन ने बांग्लादेश के लोगों के दिलों में जगह बनाई (एनडी में पूर्व में टिप्पणी में विवरण) जो बड़ी संख्या में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए बाहर आए। शेख हसीना ने बांग्लादेश पर अपना तानाशाही शासन थोप रखा था। इस व्यापक आंदोलन का उपयोग बांग्लादेश की सेना ने शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए किया। शेख हसीना 5 अगस्त को भारत भाग गईं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम प्रशासन ने सत्ता संभाली।

सत्ताहीनता के दौर में, बांग्लादेश में बहुसंख्यक समुदाय (मुस्लिमों) की सांप्रदायिक ताकतों ने अल्पसंख्यकों–हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों के घरों और धार्मिक स्थलों पर हमले किए। शुरू में यूनुस सरकार ने इसे अवामी लीग के समर्थकों पर हमले के रूप में पेश किया। कुछ छात्र समूहों ने अल्पसंख्यकों के स्थानों की रक्षा करने की पहल भी की। लेकिन अल्पसंख्यकों पर हमले जारी हैं और यूनुस सरकार उन्हें रोकने में विफल रही है या रोकना नहीं चाहती है। भारतीय मीडिया में हालांकि कुछ अतिरंजित रपटें हैं लेकिन ऐसे हमले एक तथ्य हैं। बांग्लादेश में प्रगतिशील और लोकतांत्रिक ताकतों द्वारा इन हमलों की निंदा की जा रही है। एक नई विशेषता यह है कि ढाका, चटगाँव और रंगपुर में अल्पसंख्यक हिंदुओं द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किये जा रहे हैं, जिसमें लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार चुनावों की तारीख नहीं घोषित रही है और पहले अवामी लीग के प्रभाव को खत्म करना चाहती है, जबकि वह विपक्षी बीएनपी और जमात–ए–इस्लामी को जगह दे रही है। इसके अलावा, गहराते आर्थिक संकट और धीमे पड़ते निर्यात के कारण मजदूर आन्दोलन बढ़ रहे हैं, खासकर 40 लाख से ज्यादा कपड़ा मजदूरों के संघर्ष सामने आ रहे हैं। हसीना के तानाशाही शासन को उखाड़ फेंकने के बाद भी बांग्लादेश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बांग्लादेश में स्थिति आंदोलनों के लिए अनुकूल हो रही है तथा प्रगतिशील व जनवादी ताकतों द्वारा पहलकदमी के लिए असर बढ़े हैं।

आरएसएस–बीजेपी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ इन हमलों का इस्तेमाल अपने मुस्लिम विरोधी प्रचार के लिए करने की कोशिश कर रही हैं। ये सबसे बड़े पाखंडी हैं क्योंकि ये स्वयं भारत में अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों पर हमला कर रहे हैं। असल में, बांग्लादेश और भारत दोनों की सांप्रदायिक ताकतों की हरकतें एक–दूसरे के लिए मददगार हैं। हमें इस मुद्दे को उठाते हुए आरएसएस–बीजेपी के अल्पसंख्यक विरोधी चरित्र और उनके सांप्रदायिक एजेंडे को उजागर करना चाहिए।

बांग्लादेश का घटनाक्रम अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती दरार को भी दर्शाता है, अमेरिका दक्षिण एशिया में अपनी नीतियों पर अमल अब भारत से अलग होकर कर रहा है, हसीना की जगह उसने अमेरिका समर्थक व्यक्ति को नियुक्त कराया है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद भारत द्वारा रूस से दूरी बनाने से इन्कार करने के पश्चात यह दरार बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश में इस घटनाक्रम का एक परिणाम है कि भारत और चीन के बीच तनाव कम हुआ है, सीमा पर तनाव बिंदुओं से सेना पीछे हटी हैं और कुल मिलाकर चीन के साथ तनाव में कमी आई है। कजान (रूस) में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। भारत में भी, आरएसएस–बीजेपी ने कुछ अमेरिकी समूहों और अमेरिकी प्रतिष्ठानों पर अपने खिलाफ होने का आरोप लगाते हुए हमला करना शुरू कर दिया है।

श्रीलंका :

श्रीलंका ने अपने राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव आयोजित किए। जेवीपी के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) की उम्मीदवार अनुरा दिसानायके को काफी अंतर से देश का राष्ट्रपति चुना गया। इसके बाद संसदीय चुनावों में एनपीपी ने संसद में दो तिहाई बहुमत हासिल किया। खास तौर पर जाफना में भी, जो एक तमिल बहुल इलाका है, एनपीपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। जनता विमुक्ति पेम्मना (जे.वी.पी.) एनपीपी का प्रमुख घटक है।

श्रीलंका आर्थिक पतन के दौर से गुजरा है जिसके प्रभाव आज भी मौजूद हैं। एक व्यापक जन आंदोलन (अर्गलाया) ने राजपक्षे शासन को सत्ता से उखाड़ फेंका था। एनपीपी के सत्ता में आने में अर्गलाया का प्रभाव है जिसने लोगों को शासक वर्ग की स्थापित पार्टियों से दूर कर दिया। हालाँकि, जेवीपी से विभाजित हुए संगठन, एफएसपी (फ्रंटलाइन सोशलिस्ट पार्टी) ने उस आंदोलन में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन चुनावी जन समर्थन एनपीपी जुटा पाई। जेवीपी अब वह पार्टी नहीं रही जिसने पहले 1970–71 और 1987–89 में विद्रोह किया था, दोनों बार जिसे श्रीलंका सरकार द्वारा कुचल दिया गया। बाद में जेवीपी ने सिंहली उग्र राष्ट्रवाद अपना लिया और राज्यों को अधिक सत्ता हस्तांतरण का विरोध किया। जेवीपी सरकार का हिस्सा रही है। जेवीपी ने उन नेताओं से नाता तोड़ लिया जो इसके संसदीय झुकाव के खिलाफ थे फिर जिन्होंने एफएसपी का गठन किया। कुछ प्रतीकात्मक परिवर्तनों को छोड़कर एनपीपी से किसी क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने आईएमएफ के साथ समझौते का समर्थन किया है।

श्रीलंका का घटनाक्रम शासक वर्ग के स्थापित राजनीतिक दलों से जनता के मोहभंग को दिखाता है, लेकिन संसदीय प्रणाली से नहीं। पिछले चुनावों में जेवीपी के पास केवल 3 सांसद थे और दिसानायके को पिछले राष्ट्रपति चुनावों में केवल 3 प्रतिशत वोट मिले थे, लेकिन इस राष्ट्रपति चुनाव में बहुमत और संसद में दो तिहाई से अधिक बहुमत प्राप्त करने में सफल रहे। यह लोगों द्वारा शासक वर्ग के पारंपरिक दलों को खारिज करना दिखाता है। इसने जनता की शक्तियों को प्रोत्साहन दिया है और उनमें से कुछ अब जन आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हो रही हैं।

सीरिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुए घटनाक्रम दर्शाते हैं कि वंशवादी तानाशाह शासन (श्रीलंका में परिवार नियंत्रित पार्टियां) तथा इसके साथ गहरा आर्थिक संकट एक शक्तिशाली मिश्रण है जो जनता को विद्रोह और पूर्व शासकों को खारिज करने की ओर ले जाता है।

पाकिस्तान :

पाकिस्तान में अस्थिरता और सरकार में सेना की बढ़ती भूमिका देखी जा रही है। मध्य वर्ग में व्यापक आधार वाली पाकिस्तान के शासक वर्गों की सबसे लोकप्रिय पार्टी इमरान खान की पीटीआई को पिछले चुनावों में जीतने नहीं दिया गया। पीटीआई प्रमुख इमरान खान और अन्य पीटीआई नेताओं के ऊपर कई मुकदमे थोप दिए गए हैं। पीटीआई को हाशिए पर धकेलने के लिए सभी राज्य संस्थानों को लगा दिया गया है। पीटीआई ने हाल ही में इस्लामाबाद में एक प्रदर्शन का आह्वान किया था, लेकिन इस सभा को बेरहमी से कुचल दिया गया। इसके बावजूद सरकार के लिए स्थिति आसान होती दिखाई नहीं पड़ती। गहराते आर्थिक संकट और आईएमएफ की शर्तों से लोगों पर पड़ने भारी बोझ के कारण, पाकिस्तान की जनता एक कठिन दौर से गुजर रही है। मंहगाई तेजी से बढ़ी है तथा आम लोगों का जीवन और अधिक दुष्कर हो गया है। इस बिगड़ती स्थिति के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ रहा है जिसके सेना के दमनतंत्र के जरिये नियंत्रण में रखा जा रहा है। सतह के नीचे जनता के गुस्से का लावा धधक रहा है। इस कारण पाकिस्तान की स्थिति व्यापक उथल पुथल की संभावना से भरी है।

वास्तव में, पाकिस्तान में जिसे 'एस्टेब्लिशमेंट' कहा जाता है, वह पाकिस्तानी सेना है और वही असली ताकत रखती है। दूसरी ओर, चीन और अमेरिका के आपसी अंतर्विरोध पाकिस्तान में खुलकर सामने आ रहे हैं। हाल ही में, पाकिस्तान ने रूस के साथ संबंध बेहतर किए हैं। रूस ने अफगानिस्तान के साथ भी संबंध विकसित किए हैं, जहां हाल ही में एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया और कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

म्यांमार में गृहयुद्ध जारी है :

पिछले कुछ महीनों में 2021 में म्यांमार में सत्ता हथियाने वाले सैन्य जुंटा के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह ने रफ्तार पकड़ी है। देश का आधे से ज्यादा हिस्सा कथित तौर पर विद्रोही ताकतों के कब्जे में है, जिसमें चीन, भारत और थाईलैंड की सीमाओं के नजदीक के बड़े इलाके शामिल हैं। सैन्य रूप से, विभिन्न जातीय समूहों के विद्रोही बल सबसे बड़ी लड़ाकू ताकत हैं और ये ताकतें पहले सरकार में रही एनएलडी के सशस्त्र विद्रोही बल के साथ मिलकर बहुसंख्यक 'बमर' समुदाय के बीच विद्रोह को एक बड़ा जनाधार दे रही हैं। विद्राही सैन्य बल न केवल व्यापक ग्रामीण अंचलों पर नियंत्राण कर रहे हैं बल्कि कई शहर भी उनके नियंत्रण में आ गये हैं तथा कई स्थानों पर फौजी कैम्पों पर भी विद्रोही ताकतों ने कब्जा कर लिया है। सत्ता के मुख्य शहरी केन्द अभी भी सेना के कब्जे में हैं।

जहां पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियाँ सैन्य शासकों (जुंटा) का विरोध करते हुए एनएलडी का समर्थन कर रही हैं, चीन ने सैन्य जुंटा और जातीय अल्पसंख्यकों के विद्रोही बलों दोनों के साथ अपने चैनल खुले रखे है। रुस जिसका प्रभाव न्यांमार में कम है सैन्य शासकों से करीबी बनाये हुए है। भारत सरकार सैन्य शासकों तथा एन.एल.डी. के साथ सम्बंध बनाये हुए है। भारत की म्यांमार के साथ एक लंबी सीमा है। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के विद्रोही बलों के नियंत्रण में आने ने भारत सरकार की चिंता बढ़ा दी है। निश्चय ही इसका असर भारत के उत्तरपूर्वी क्षेत्रों पर पड़ेगा जहां शासक आर.एस.एस.–भाजपा की नीतियों ने इन क्षेत्रों की जनता के विभिन्न हिस्सों के बीच वैमनस्य तथा उत्तरपूर्व के प्रांतों में तनाव को बढ़ाया है।

नेपाल, मालदीव और भूटान की घटनाओं से भी भारत सरकार इस क्षेत्र में और अलग–थलग पड़ती जा रही है। कम से कम, उसके बड़े भाई वाले रवैये का पड़ोसी देशों द्वारा विरोध बढ़ता जा रहा है। बेहतर होगा कि भारत सरकार सार्क के प्रति अपने विरोध को त्याग दे और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर करे।

पत्रिका के नियमित प्रकाशन के लिए सभी पाठकों से अनुरोध

- *पत्रिका के लिए लेख व रिपोर्ट नियमित रूप से भेजें।*
- *पत्रिका के बारे में अपने सुझाव भेजें।*
- *कृपया पत्रिका की प्रतियों की राशि समय पर पहुंचाएं।*
- *लेख, रिपोर्ट, सुझाव तथा राशि पत्रिका के पते पर भेजें।*

केन्द्रीय बजट 2025-'26

(पृष्ठ 1 का शेष)

है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने के बजाय राजधानी दिल्ली में चुनावी गणित से प्रेरित है, जैसा कि इस संबंध में किसी अन्य उपाय की कमी से स्पष्ट है। यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों के संबंध में भी सरकार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने से इनकार कर रही है और सशस्त्र बलों के संबंध में अपनी अग्निपथ योजना जारी रखे हुए है। जिन क्षेत्रों पर बड़ी संख्या में लोग रोजगार और आय के लिए निर्भर हैं, यानी कृषि व एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) की उपेक्षा जारी है, जबकि सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च में वास्तव में कटौती की गई है, वह भी अगर औपचारिक रुप से नहीं तो कम से कम वास्तविक रूप में। सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय में कटौती लोगों के साथ बड़ा धोखा है, जो बजट में आवंटित राशि को भी खर्च नहीं करने में भी प्रकट होता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था अर्ध–औपनिवेशिक बंधनों और अर्ध–सामंती सीमाओं में फंसी हुई है। जबकि लोगों पर कर का बोझ, विशेष रूप से अप्रत्यक्ष कर जो गरीबों पर असमान रूप से पड़ता है, ऊंचा बना हुआ है, भारतीय सरकार वाशिंगटन में नये प्रशासन द्वारा भारत सहित कई व्यापार भागीदारों के साथ अपने व्यापार घाटे को कम करने पर जोर देने वाले के प्रति सावधान रही है। एक निवारक उपाय के रूप में, सरकार ने कुछ प्रकार के भारी वाहनों और सौर पैनलों जैसे अमेरिका से आयात पर शुल्क कम कर दिया है। साथ ही बीमा क्षेत्र को 100 प्रतिशत विदेशी निवेश के लिए खोल दिया है। यह इस बात का संकेत देता है कि भारत सरकार ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारत को अपनी महंगी वस्तुएं खरीदने के लिए मजबूर करने के दबाव के सामने क्या रुख अपनायेगी।

ऐसे कोई उपाय नहीं किए गए हैं जो लोगों के भारी बहुमत– औद्योगिक श्रमिकों, कृषि मजदूरों और किसानों की क्रय शक्ति को बढ़ा सकें। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया है यहां तक कि गिग वर्करों के लिए भी वित्त मंत्री ने केवल पीएमजेएवाई के तहत कवरेज की घोषणा की और कुछ नहीं। दूसरी ओर, सरकार चार श्रम संहिताओं को लागू करने पर आमादा है, जो श्रमिकों के संगठित होने और संघर्ष करने के अधिकारों की जड़ पर प्रहार करते हैं, जो अब तक प्रति मजदूरों ने जो कुछ भी हासिल किया है, उसके लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। एमएसएमई जो औद्योगिक रोजगार का सबसे बड़ा हिस्सा प्रदान करते हैं, को एक बार फिर से नजरअंदाज कर दिया गया है और केवल ऋण राशि में वृद्धि की गई है। उन्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वह है सुनिश्चित बाजार, जिसे विदेशी और घरेलू कॉरपोरेट के अधीन यह सरकार प्रदान करने से कतराती है।

बजट में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को दरकिनार किया गया है। एकमात्र वृद्धि केसीसी के तहत ऋण की राशि (3 लाख से 5 लाख तक) में है, जबकि किसान बढ़ते कर्ज और व्यापार की प्रतिकूल शर्तों से पीड़ित हैं। सरकार एमएसपी पर पूर्ण खरीद सुनिश्चित करने, सभी फसलों को एमएसपी के तहत लाने और स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी तय करने का विरोध कर रही है। यद्यपि देश खाद्य तेल और दालों के आयात पर बड़ी रकम खर्च करता है, लेकिन उचित उपायों के माध्यम से देश में उनकी खेती को बढ़ावा देने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। बल्कि उर्वरकों, ईंधन और ग्रामीण विकास के लिए आवंटन में वास्तविक रूप से कटौती की गई है। कृषि अनुसंधान के लिए आवंटन बहुत कम है। दूसरी ओर पीएमएफबीवाई (फसल बीमा) के लिए आवंटन कम कर दिया गया है।

ग्रामीण विकास के लिए आवंटन कम कर दिया गया है। जहां भूमि सुधारों को व्यावहारिक रूप से त्याग दिया गया है, ग्रामीण गरीबों के लिए योजनाएं कम कर दी गई हैं। खाद्य सब्सिडी में कटौती की गई है और मनरेगा के आबंटन में कोई वृद्धि नहीं की गई है। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक बेरोजगारी जो अल्परोजगार के रूप में छिपी हुई है, की समस्या को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं। आवास (4.38 प्रतिशत), एससी/एसटी आवंटन (3 प्रतिशत) सहित सभी सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च में कटौती की गई है।

इस बजट में बहुत अधिक जुमले इस्तेमाल किए गए हैं परंतु हकीकत में कुछ नहीं किया गया है। शिक्षा के लिए आबंटन कम रहा है, बल्कि सकल घरेलू उत्पाद और बजट में शिक्षा के लिए आबंटन के प्रतिशत में कमी आई है जैसा कि 7.6% वृद्धि से स्पष्ट है, जबकि अनुमानित आर्थिक वृद्धि 10.1% है। शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण हो रहा है, जो इसे बहुसंख्य लोगों की पहुंच से बाहर कर जा रहा है। शासकों के हितों की सेवा के लिए सांप्रदायिकरण किया जा रहा है। 10,000 मेडिकल सीटों की वृद्धि की घोषणा की गई है, लेकिन इसके लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। इसका मतलब है कि यह वृद्धि निजी कॉलेजों में होगी। यहां तक कि सरकार द्वारा शुरू किए गए मेडिकल कॉलेजों में भी शिक्षा के स्तर को बनाए रखने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

आर्थिक संकट गहरा रहा है, यह बजट अनुमानों से भी स्पष्ट है। व्यय का एक चौथाई से अधिक हिस्सा सरकार द्वारा ऋणों पर ब्याज भुगतान को पूरा करने में चला जाता है। यह सरकार पीपीपी मोड के माध्यम से बुनियादी ढांचे पर खर्च कर रही है, जिससे सरकारी खर्च के माध्यम से अपने कॉरपोरेट मित्रों को लाभ दे रही है। हालांकि, इस वर्ष सड़क परिवहन और रेलवे के लिए आबंटन समान रहे हैं, यानी वास्तविक रूप से कम हो गए हैं। यहां तक कि पूंजीगत व्यय में भी केवल 5% की वृद्धि की गई है, जो वास्तविक रूप से कमी है। मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया बजट बिगड़ती आर्थिक स्थिति को छिपाने और कल्याणकारी उपायों में कटौती करने का प्रयास है, जबकि आम लोगों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा दिखाई गई है। सरकार ने लोगों की चिंताओं को दरकिनार कर दिया है। लोगों को इस बजट और उन पर बढ़ते बोझ का पुरजोर विरोध करना चाहिए।

सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी

2 फरवरी, 2025

पंजाब : बेचिराग गांव के दलितों द्वारा चिराग जलाकर 927 एकड़ जमीन पर कब्जा

मालवा के हजारों दलित मजदूरों और भूमिहीन किसानों ने बेचिराग गांव की 927 एकड़ भूमि पर अपना दावा जताते हुए चिराग (दिया) जला कर जमीन पर अपने कब्जे की घोषणा की। साथ ही बेचिराग गांव का नाम अब से बेगमपुरा करने का भी ऐलान किया है। भारी वर्षा और खराब मौसम के बावजूद मालवा के दलित समुदाय के हजारों लोग भटिंडा–जीरखपुर हाईवे के पास एकत्र हुए और उक्त जमीन के हिस्से पर दावा करने के लिए मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी के जोनल अध्यक्ष मुकेश मलौद ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि हजारों दलितों ने बेचिराग गांव में दिया जलाकर गांव को बेगमपुरा बनाने की घोषणा की है।

जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी के झंडे तले प्रदर्शन करते बेचिराग गांव में हजारों दलित जिन्होने जमीदारों के अवैध कब्जे की 927 एकड़ जमीन पर कब्जा किया

जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी के जोनल वित्त सचिव बिक्कर सिंह हथोआ और उपाध्यक्ष धर्मवीर हरिगढ़ ने मार्च में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही सरकारें भूमि परिसीमन अधिनियम 1972 बनाकर भूमि सुधारों के दावे कर रही हों, लेकिन आज भी हजारों एकड़ जमीन बड़े–बड़े जमींदारों के कब्जे में है और दलितों के पास सिर ढ़ंकने के लिए अपना एक घर भी नहीं है। यही नहीं आज भी किसी दलित महिला को दूसरों (जमींदारों) की जमीन पर जाने पर हर तरह का शोषण किया जाता है। जोनल अध्यक्ष मुकेश मलौद और जगतार तोलेवाल ने कहा कि जातिगत उत्पीड़न को खत्म करने और भूमि के असमान वितरण को समाप्त करने के लिए अब संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि बेचिराग गांव में जींद रियासत के राजा की 927 एकड़ भूमि जिस पर बड़े जमींदारों का अवैध कब्जा है, उसको बेगमपुरा गांव के नाम से दलितों, भूमिहीनों व छोटे किसानों में बांटने की घोषणा की।

मार्च के दौरान वहां उपस्थित हजारों लोगों ने इस भूमि पर दिया जलाकर घोषणा की कि अब इस भूमि पर दलित परिवारों का हक है और गेहूं की मौजूदा फसल कटने के बाद कोई भी व्यक्ति इस भूमि पर खेती नहीं कर सकेगा, क्योंकि यह भूमि दलितों और भूमिहीनों में बराबर–बराबर बांटी जाएगी और दलित परिवार ही इस पर संयुक्त खेती कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि बेचिराग गांव के अलावा पंजाब में सैकड़ों बेचिराग गांव हैं, जिनकी भूमि पर बड़े जमींदारों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने पंजाब सरकार से मांग की कि भूमि परिसीमन अधिनियम 1972 को तुरंत लागू किया जाए तथा इसके अनुसार जमीदारों के पास साढ़े 17 एकड़ से अधिक भूमि दलितों, भूमिहीनों व छोटे किसानों में वितरित की जाए।

मुकेश मलौद के अलावा इस अवसर पर गुरविंदर बौर, शिंगारा सिंह हेडिके, गुरविंदर शादीहारी, गुरु चरण सिंह ग्राचो, गुरदास जालूर और जसवीर कौर हेड़िके आदि नेताओं ने संबोधित किया।

ओडिशा : स्वच्छताकर्मियों का विशाल प्रदर्शन

ओडिशा के विभिन्न जिलों के शहरी निकायों (यूएलबी) जैसे नगर निगम, नगर पालिका और अधिसूचित क्षेत्र परिषदों के सफाई कर्मियों के साथ अन्य कल्याणकारी कार्यों में लगे हजारों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 17 फरवरी 2025 को भुवनेश्वर में विधानसभा तक मार्च निकाला। इनमें स्वच्छता साथी, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मचारी और स्वच्छ शबरी कार्यक्रम के कर्मचारी शामिल थे। इन योजनाओं में लगे हजारों कर्मचारी जो गत कई वर्षों से स्वच्छ भारत अभियान योजना के तहत सफाई कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें ना तो न्यूनतम वेतन मिल रहा है ना ही पीएफ, ईएसआई जैसे आवश्यक श्रमिक अधिकारों और योजनाओं का लाभ पाने का अधिकार है। यही नहीं सरकार इन कर्मचारियों को अपना कर्मचारी भी नहीं मान रही है और ना ही उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं दे रही है।

ओडिशा के इन स्वच्छता कर्मियों और पर्यवेक्षकों को राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हालांकि पिछली सरकार ने स्वच्छता साथियों का वेतन रु.4000 से बढ़ाकर रु. 8000 और स्वच्छता पर्यवेक्षकों का वेतन रु.8000 से बढ़कर रु.12000 कर दिया था, लेकिन आरएसएस–भाजपा की नई सरकार इसका भुगतान करने से इनकार कर रही है। इसके विपरीत उड़ीसा सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए कई कठोर शर्तें रख दी हैं। जैसे प्रत्येक महीने शहरी परिवारों से एक निश्चित प्रतिशत का उपयोगकर्ता शुल्क वसूलना, अन्यथा उन्हें उनका पिछला वेतन भी नहीं दिया जाएगा। इसी तरह कुछ शहरी स्थानीय निकायों में मासिक वेतन पाने के लिए स्थानीय पार्षद का हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया गया है। वार्ड समन्वयक नामक एक अन्य श्रेणी का चयन पिछली सरकार ने वार्ड कार्यालय में वार्ड स्तर पर नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करने के लिए किया था।

नयी सरकार ने राजनीतिक कारणों से उनकी नियुक्ति रोक दी है। चूंकि इन कर्मचारियों को पिछली बीजू जद की नवीन पटनायक सरकार के कार्यकाल में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से चुना गया था, इसलिए आरएसएस–भाजपा की सरकार नए चयन प्रक्रिया द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अपने समर्थकों को नियुक्त करने की योजना बना रही है। इसीलिए वे 2 साल से अधिक समय से इंतजार कर रहे हैं और यूएलबी का विकास कार्य प्रभावित है। यूएलबी के अधिकांश नियमित कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत हो चुके हैं और उनकी जगह को पूरा करने के लिए कोई नहीं भर्ती नहीं की गई है। इन जायज मांगों को लेकर हजारों सफाई कर्मचारियों और वार्ड समन्वयकों ने राज्य विधानसभा के सामने इकट्ठा होकर राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। इन कर्मचारियों के 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने इफ्टू राज्याध्यक्ष कामरेड प्रताप प्रधान के साथ राज्य नगर प्रशासन के निदेशक के साथ विस्तृत चर्चा की और उन्होंने विधानसभा सत्र के बाद उनकी अधिकांश मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है।

आपरेशन "कगार"

पंजाब : क्रांतिकारी तथा जनवादी संगठनों द्वारा आदिवासियों की हत्याओं के विरुद्ध प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न इलाकों में जल, जंगल, जमीन और रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे आदिवासियों और अन्य तबकों के खिलाफ ऑपरेशन "कगार" के तहत हो रही पुलिस मुठभेड़ों के नाम पर की जा रही हत्याओं और सभी तरह के उत्पीड़नों को रोकने के लिए क्रांतिकारी व लोकतांत्रिक पार्टियों और जन संगठनों ने पंजाब के सभी जिलों में 28 फरवरी 2025 को व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। इन विरोध प्रदर्शनों को संयुक्त रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी लेनिनवादी) न्यू डेमोक्रेसी, आरएमपीआई और रिवॉल्यूशनरी सेंटर पंजाब ने आयोजित किया था। मुख्य रूप से जालंधर, कपूरथला, अमृतसर, गुरदासपुर, शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना, मोगा, फरीदकोट, संगरूर और पटियाला सहित पंजाब के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। विरोध प्रदर्शनों, मार्च, और सभाओं के बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारियों को सौंपे गए।

राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापनों में मांग की गई है कि आदिवासियों और अन्य तबकों के खिलाफ ऑपरेशन कगार के नाम पर हो रही फर्जी पुलिस मुठभेड़ों को तुरंत रोका जाए, खनिज संपदाओं से युक्त पहाड़ी और वन क्षेत्रों को देशी–विदेशी कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपना बंद किया जाए, जनजातीय क्षेत्रों से सेना व अर्धसैनिक बलों को तुरंत हटाया जाए, इन उत्पीड़नों का विरोध करने वाले संगठनों, पार्टियों व राजनीतिक और लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, लेखकों तथा बुद्धिजीवियों को "अर्बन नक्सल" के नाम से संबोधित कर उनके ऊपर किये जा रहे दमन को रोका जाए और ऑपरेशन कगार को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। इस अवसर पर कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव बंत सिंह बराड़, सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी के राज्य नेता कामरेड अजमेर सिंह, आरएमपीआई के राज्य सचिव परगट सिंह जामराय तथा रिवॉल्यूशनरी सेंटर पंजाब के राज्य अध्यक्ष नारायण दत्त सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया।

पंजाब के विभिन्न जिलों में हुए विरोध प्रदर्शनों को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि पिछले वर्ष सुरक्षा बलों द्वारा 250 लोगों की हत्या की गई तथा इस वर्ष के पहले 6 सप्ताह में ही 86 लोगों की हत्याएं मुठभेड़ों के नाम पर की जा चुकी है। हाल ही में घटित हुई ताजा घटना छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की है, जहां 31 आदिवासियों की हत्या कर दी गई।

खनिज संपदाओं से भरपूर पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों से शताब्दियों से रह रहे आदिवासियों और ग्रामीण आबादी को उजाड़ कर देश–विदेश के कारपोरेट्स, साम्राज्यवादियों और औद्योगिक समूहों को सौपा जा रहा है तथा आम लोगों को आतंकित किया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि संविधान में निहित कानूनी प्रावधानों का पालन न करके कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए गठित "मूलवासी बचाओ मंच" को अवैध घोषित कर उसके नेताओं को जेल में डाल दिया गया है और लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के कानूनी अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है। पूर्व में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि अगर निर्दोष आदिवासियों को जेलों में बंद कर दिया जाएगा, तो उनके पास माओवादियों में शामिल हो जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा।

विरोध प्रदर्शनों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कॉरपोरेट लूट और सत्ता के उत्पीड़न का विरोध करने वाले क्षेत्रों से मार्च 2026 तक नक्सलियों को खत्म करने की घोषणा राजनीतिक हिंसा का क्रूर प्रकटीकरण है, जिसके तहत कानून के अनुसार शासन करने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इस नीति के तहत उत्पीड़न का विरोध करने वाले संगठनों, दलों, राजनीतिक और लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों व लेखकों को भी शहरी नक्सली कहकर निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए देश भर में विरोध की आवाज उठाने और संघर्षरत लोगों को विभिन्न तरीकों से दबाने की हर कोशिशों का जबरदस्त और व्यापक विरोध करना आज बेहद जरूरी हो गया है। वक्ताओं ने सरकार के इन अलोकतांत्रिक और फासीवादी हमलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर देश भर में लामबंद होकर कड़ा विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान भी किया है।

वहीं जालंधर में हुए प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों को कामरेड तरसेम पीटर, हंसराज पबवान, रछपाल कैली, हरजिंदर सिंह मौजी, कश्मीर सिंह घुग्गशोर और संदीप अरोड़ा सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। विरोध सभा करने के बाद देशभगत यादगार हाल से रैली निकाल कर राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया।

हैदराबाद रैली

(पृष्ठ 1 का शेष)

प्रशासन के नाम पर आवेदन करने के बाद सेवा में दोबारा आवेदन लेने की क्या जरूरत है? आवेदनों को वापस भेजे जाने से गरीब लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में मुठभेड़ और साजिश के मामले इस बात का सबूत है कि सातवीं गारंटी जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से संबंधित है उसे लागू नहीं किया जा रहा है। लोकतांत्रिक शासन लागू नहीं होने के कारण लागाचर्ला आदिवासी किसानों के खिलाफ अवैध मामले दर्ज किए गए हैं और उन्हें जेल में डाल दिया गया है। वक्ताओं ने मांग की कि सरकार श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाये और बीड़ी श्रमिकों को जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान करे। इसके अलावा ऑटो चालकों को सहायता प्रदान करे। सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी नेताओं ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है यदि लोगों से किए गए सभी वायदों को लागू नहीं किया गया, तो तेलंगाना में बड़ा जन आंदोलन शुरू होगा।

विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश में सी.पी.आई. (एम-एल) न्यू डेमोक्रेसी द्वारा एकीकरण सभा

28–12–2024 को हैदराबाद में आयोजित विलय बैठक के माध्यम से भाकपा (माले)–न्यू डेमोक्रेसी के एकीकरण की सार्वजनिक घोषणा के बाद, 23 फरवरी 2025 को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश राज्य में एक राज्य स्तरीय एकता बैठक बहुत

सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

इस एकता बैठक में राज्य के सभी जिलों से 600 से अधिक साथियों ने भाग लिया। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत काफी संख्या में थी, हालांकि यह अभी भी अल्पमत में थी। सभा में भाग लेने आये अधिकांश प्रतिभागी बुनियादी वर्गों, यानी किसान, कुली और मजदूरों से आए थे।

बैठक शुरू होने से पहले आसपास की गलियों में रैली निकाली गई। मीटिंग हॉल में जाने से पहले पार्टी के राज्य प्रवक्ता का. पी. प्रसाद ने पार्टी का झंडा फहराया। अरुणोदय टीमों ने एक गीत गाया।

बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राज्य प्रवक्ता कॉमरेड चिट्टीपाटी वेंकटेश्वरलू ने की। कॉमरेड चिट्टीपाटी ने पहले शहीदो की स्मृति में शोक प्रस्ताव पेश किया और सदन में मौन रखा गया। अरुणोदय सांस्कृतिक टीम द्वारा शहीदों पर एक गीत गाया गया। कॉमरेड चिट्टीपाटी ने इस एकता बैठक की पृष्ठभूमि के बारे में बताया।

कॉमरेड एस. वेंकटेश्वर राव (एसवी) पार्टी सीसी सदस्य ने फासीवाद के खतरे के कारण मार्क्सवाद–लेनिनवाद माओ विचार पर आधारित क्रांतिकारी दलों के बीच एकता और विलय की ऐतिहासिक और राजनीतिक आवश्यकता के बारे में बात की। तेलंगाना के पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता कॉमरेड जे.वी. चलपति राव ने अपने वक्तव्य में विलय की पृष्ठभूमि और बदलती परिस्थितियों के आधार पर पार्टी के विकास की प्रक्रिया के बारे में बताया। क्रांतिकारी अमल के बारे में बताया और बताया कि कैसे बाद में गलत प्रवृत्तियों ने इसे बाधित किया। उन्होंने सदन से उन समस्याओं को दूर करने और इस विलय के आलोक में पार्टी बनाने की शपथ लेने की अपील की।

पार्टी के राज्य नेता कॉमरेड पोलारी ने पहले वक्ताओं को आमंत्रित किया और उन्होंने भी विचार रखे। पार्टी की केंद्रीय समिति के वरिष्ठ नेता कॉमरेड वाई. संबाशिव राव को भी वक्ता के रूप में शामिल होना था। लेकिन उस समय उनकी स्वास्थ्य स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे यात्रा कर सकें इसलिए वे उपस्थित नहीं हो सके। विजाग, ओंगोल, अनंतपुरम, श्रीकाकुलम, पश्चिम गोदावरी जिलों से अरुणोदय टीमों ने भाग लिया। उन्होंने गीत गाए और कुछ नाटक प्रस्तुत किये।

बैठक लगभग 11:30 बजे शुरू हुई और 2:30 बजे समाप्त हुई। इन 3 घंटों के दौरान, श्रोताओं ने उत्सुकता से भाषण ध्यान से सुने। प्रतिभागियों ने कार्यवाही पर पूरा ध्यान दिया। इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। इस एकता बैठक ने पार्टी के रैंकों और फाइलों में बहुत उत्साही माहौल बनाया है। यह न केवल भाषणों को सुनने के माध्यम से, बल्कि लंबे समय के बाद एक–दूसरे को देखने और अभिवादन करने के माध्यम से भी देखा गया। लगभग 12 साल का बुरा और दुखद दौर, 2013 में पार्टी के विभाजन के बाद से गुजरा। उस दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रिय विभाजन ने

(शेष कालम 4 पर)

सासाराम (बिहार) के ऐतिहासिक तालाबों को बचाने धरना

सासाराम–रोहतास के ऐतिहासिक महत्व वाले तालाबों को नष्ट कर स्थानीय भू माफिया जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये तालाब ऐतिहासिक महत्व के ही नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों से शहर की आबादी को जल उपलब्ध कराने के साथ ही पर्यावरण व सौंदर्य में भी इजाफा करते रहे हैं। सासाराम–रोहतास शेरशाह सूरी द्वारा बसाया गया था, जो बाद में दिल्ली का बादशाह भी बना। उस समय उसके कार्यकाल में बहुत सारे तालाब, इमारतें, सराय और सड़कें बनवाई गई थीं। उसके बाद भी कई अन्य राजाओं, जमींदारों और सेठों ने समाज कल्याण व धार्मिक भावनाओं के चलते मंदिर और तालाबों का निर्माण कराया था। आज उन सभी पर अवैध कब्जा किया जा रहा है।

इसके खिलाफ 15 फरवरी 2025 को सासाराम–रोहतास के प्रगतिशील, लोकतांत्रिक, जनवाद पसंद नागरिक संगठनों के साझा मंच 'जनमंच सासाराम' ने जन प्रतिरोध धरने का आयोजन किया, जिसमें 700 से अधिक लोग उपस्थित थे। जन प्रतिरोध धरना 11 बजे दिन से लेकर शाम 4 बजे तक चला। बाद में प्रदर्शनकारियों ने जिले के प्रभारी अपर अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

सासाराम–रोहतास के नागरिक संगठनों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन में मांग की है कि मोहन साव तालाब पर किए गए अवैध कब्जों व भू माफियाओं को हटाया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वहां के पुराने घाट और प्राचीन मंदिर को संरक्षित किया जाए। इसके अलावा सलीम शाह तालाब, जिला परिषद तालाब, सागर तालाब, बलडिहवा तालाब, चलनिया रामेश्वर गंज तालाब, अलावल खान तालाब, नक्टा तालाब सहित शहर के सभी जल स्रोतों को अधिग्रहित कर संरक्षित किया जाए। ज्ञापन में मांग की गई है कि सासाराम ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्व का शहर रहा है। इसलिए उसके संरक्षण और रखरखाव के लिए प्रशासन को तत्काल उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा शहर के जल पर्यावरण एवं ऐतिहासिक धरोहरों को नष्ट करने की हर कोशिश के खिलाफ जनमंच सासाराम आंदोलन शुरू करेगा।

इससे पूर्व जन प्रतिरोध धरने की अध्यक्षता कम्युनिस्ट सेंटर आफ इंडिया की केंद्रीय कमेटी के सदस्य भोला शंकर और संचालन सीपीआई एमएल लिबरेशन के जिला सदस्य रविशंकर राम ने किया। दिन भर चले धरने के दौरान सभा को अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के जिला सचिव अयोध्या राम, जन अधिकार मंच सासाराम के संयोजक शिव शंकर सिंह कुशवाहा, जनवादी ऑटो–ई रिक्शा चालक मजदूर संघ के दिनेश कुमार, एआईकेएमएस के राजेश पासवान, सीसीआई के अशोक कुमार, वंचित समाज मोर्चा के संजय यादव और लल्लन राम आदि नेताओं ने संबोधित किया।

सासाराम और रोहतास में काफी समय से स्थानीय नागरिक तालाबों, पर्यावरण और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर चिंतित और आक्रोशित हैं। यही कारण है कि बहुत कम समय में सैकड़ों लोग जुलूस बनाकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए और धरना दिया।

जन प्रतिरोध धरने को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें जल जीवन और हरियाली के नाम पर गरीब लोगों के घर और बस्तियों को उजाड़ देते हैं, लेकिन सैकड़ों वर्षों से बने पुराने तालाबों व जल स्रोतों के जीर्णोद्धार की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, बल्कि उन ऐतिहासिक तालाबों और इमारतों को नष्ट कर कब्जा करने वाले भू माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र या राज्य सरकारों की नदी, तालाब और जल स्रोतों के रखरखाव व संरक्षण के प्रति कोई ठोस नीति नहीं है। गंगा व अन्य नदियों की सफाई योजना के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए की लूट होती है। सासाराम नगर निगम क्षेत्र में भी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के तालाब और इमारतें नष्ट होती जा रही हैं। वक्ताओं ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो जल संरक्षण और प्राचीन तालाबों को बचाने के लिए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की जायेगी।

उक्त सभा को संबोधित करते हुएं वक्ताओं ने यह भी बताया कि मोहन साह तालाब स्थानीय नागरिकों के लिए जल का ही सवाल नहीं है, बल्कि वहां एक प्राचीन मंदिर भी हैं। ऐसे में जन प्रतिरोध धरना के माध्यम से जनता प्रशासन और सरकार की आंख खोलना चाहती है कि यदि जल्द ही उसने ठोस कदम नहीं उठाए, तो एक व्यापक आंदोलन छेड़ा जायेगा।

आंध्र प्रदेश में सी.पी.आई. (एम-एल) न्यू डेमोक्रेसी द्वारा एकीकरण सभा

(कालम 2 का शेष)

कार्यकर्ताओं के बीच खाई और अंतराल पैदा कर दिया था। दरअसल, ये सभी साथी 2013 से पहले एक ही पार्टी में काम करते थे। लेकिन अलग–अलग पार्टियों में वे बंटे हुए थे और एक–दूसरे के खिलाफ भी खड़े थे।

यह संगठनात्मक रूप से एकता बैठक है, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह पुराने साथियों और मित्रों की पुनर्मिलन बैठक या एक साथ आना है। बैठक स्थल पर साथियों के बीच प्यार और स्नेह के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाने का नजारा देखने को मिला। यह एकता की भावना कार्यकर्ताओं को नई राजनीतिक ताकत और इच्छाशक्ति देती है। नेताओं द्वारा एकता के बारे में भाषणों के अलावा 12 साल के बुरे दौर कि बसउद हुई एकता पर एक–दूसरे को बधाई और गले लगाने से भी नई राजनीतिक भावना मिलेगी और क्रांतिकारी आंदोलन को मजबूत करने, और मजबूत करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा।

किसान नेताओं द्वारा आंशिक खरीद के प्रस्ताव की आलोचना, चंड़ीगढ़ धरने की तैयारी तेज

कीर्ति किसान यूनियन (केकेयू) ने 5 मार्च से चंडीगढ़ में होने वाले धरने की तैयारियों की समीक्षा की। धरने में सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ हजारों किसान भागीदारी करेंगे। केकेयू ने पंजाब सरकार से विधानसभा सत्र बुलाकर राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति के मसौदे को खारिज करने की मांग की है। केकेयू ने स्पष्ट घोषा की कि एमएसपी पर आंशिक खरीद (25 प्रतिशत) की गारंटी देने वाला, कानून जैसा कोई किसान विरोधी समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसान संगठन की मांग है कि सरकार बासमती, मक्का, मूंग, आलू, मटर और गोभी की एमएसपी घोषित करे और खरीद की गारंटी दे। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार की गई मांगों को लागू करने जैसे मुद्दे भी धरने की मांग में शामिल है। किसान संगठन की राज्य कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष निर्भय सिंह ढुडिके की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि कीर्ति किसान यूनियन–संयुक्त किसान मोर्चा 5 मार्च से चंडीगढ़ में होने वाले अनिश्चितकालीन धरने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा।

केकेयू के राज्य महासचिव राजिंदर सिंह दीपसिंहवाला और प्रदेश के प्रेस सचिव रामिंदर सिंह पटियाला ने बैठक के बाद बताया कि केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच एमएसपी और खरीद गारंटी कानून को लेकर चल रही बातचीत में 25–30 प्रतिशत फसलों की आंशिक सरकारी खरीद के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और फैसला किया है कि संगठन सभी फसलों के पूरे उत्पादन की खरीद की गारंटी का कानून बनाने के पक्ष में मजबूती से खड़ा है। बैठक के बाद एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि आंशिक खरीद की गारंटी कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का मामला है। आंशिक खरीद पंजाब–हरियाणा में एमएसपी पर खरीदे जा रहे गेहूं और धान की खरीद को कम करने की दिशा में ले जाएगा। बैठक में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि कीर्ति किसान यूनियन ऐसे किसी भी किसान विरोधी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा।

बैठक में राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति के मसौदे को केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र पर कॉरपोरेट नियंत्रण स्थापित करने का एक और प्रयास करार दिया गया तथा इसे रद्द करवाने के लिए जोरदार संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार द्वारा खाद्यान्नों के विपणन एवं वितरण की पूरी प्रक्रिया को कॉरपोरेट घरानों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने के उद्देश्य से लाए गए इस मसौदे को सहकारिता के क्षेत्र में राज्यों के अधिकारों को खत्म करने की जानबूझकर की गई चाल करार दिया गया है।

बयान में मांग की गई है कि पंजाब सरकार विधानसभा का सत्र बुलाकर इस मसौदे को रद्द करवाने के लिए प्रस्ताव पारित करे। किसान संगठन द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया है कि चंडीगढ़ धरने में इस मसौदे को रद्द करवाने के साथ–साथ पंजाब सरकार से बासमती, मक्का, मूंग, आलू, मटर तथा गोभी आदि की एमएसपी पर खरीद की गारंटी की भी मांग की जाएगी। बयान में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने के 5 मिनट के भीतर पंजाब के किसानों को एमएसपी देने का वायदा किया था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बावजूद कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि गन्ना मिलों के पास किसानों का बकाया ब्याज सहित देने पर भी पंजाब सरकार चुप्पी साधे बैठी है।

किसान नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार 19 दिसंबर 2023 को संयुक्त किसान मोर्चा के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा की गई बैठक में सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत की गई मांगों को भी लागू करने में विफल रही है, जिसमें सहकारी संस्थाओं में एकमुश्त कर्ज निपटान योजना शुरू करना और सहकारी समितियों में नए खाते खोलने की अनुमति देना शामिल है। किसान नेताओं ने कहा कि चंडीगढ़ धरने में किसानों को मलिकाना हक देने, हर खेत तक नहरों का पानी देने और हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की मांग को भी जोरदार तरीके से उठाया जाएगा।

पश्चिम बंगाल

आलू किसानों की मांग पर ग्रामीण सड़क जाम

पश्चिम बंगाल में आलू किसानों की गंभीर स्थिति के संदर्भ में, जहां उन्हें केवल 600–700 रुपये प्रति क्विंटल की बहुत कम कीमत मिल रही है, पश्चिम बंगाल SKM ने 28 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूरे राज्य में ग्रामीण सड़क अवरोध करने का आह्वान किया था।

28 फरवरी को जलपाईगुड़ी जिले में 2 स्थानों, अलीपुरद्वार जिले में 1 स्थान, उत्तर दिनाजपुर जिले में 2 स्थानों, नदिया जिले में 1 स्थान, उत्तर 24 परगना जिले में 1 स्थान, बर्दवान जिले में 12 स्थानों, बांकुड़ा जिले में 2 स्थानों, पश्चिम मेदिनीपुर जिले में 2 स्थानों, दक्षिण 24 परगना जिले में 1 स्थान, हुगली जिले में 2 स्थानों और हावड़ा जिले में 1 स्थान पर सड़क अवरोध किया गया।

पश्चिम बंगाल SKM की मुख्य मांग है आलू के लिए 1300 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)। (गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 900 रुपये प्रति क्विंटल का MSP घोषित किया है)। साथ ही, सरकार को सभी अनबिके आलू (जो बिक्री के लिए उपलब्ध हैं) की खरीद करनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल SKM ने 100 दिन के मनरेगा कार्य को तुरंत बहाल करने, इसे 200 दिन करने और मजदूरी 600 रुपये प्रति दिन देने की मांग की है। (ध्यान देने योग्य है कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के नाम पर पिछले तीन वर्षों से पश्चिम बंगाल में मनरेगा के लिए केंद्रीय अनुदान बंद कर रखा है)।

साथ ही मांग की गई कि NPFAM (नए कृषि कानून) को खारिज किया जाए और राज्य सरकार को विधानसभा सत्र में इस संबंध में तुरंत प्रस्ताव पारित करना चाहिए।

एआईकेएमएस की केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा पंजाब में किसान नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा

(अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा (एआईकेएमएस) की केन्द्रीय कार्यकारिणी के 4 मार्च 2025 को जारी बयान को यहां प्रकाशित किया जा रहा है। यह बयान एआईकेएमएस के अध्यक्ष का. वी. वैंकटरमैया तथा महासचिव का. आशीष मित्तल द्वारा जारी किया गया।)

– एआईकेएमएस ने पंजाब एसकेएम के पचासों नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा की।

– आप पार्टी आरएसएस, भाजपा की कारपोरेट व एमएनसी समर्थक कृषि मार्केटिंग नीति के पक्ष में है।

– तुरंत रिहाई की जाए, नहीं तो देशव्यापी विरोध का सामना करे।

एआईकेएमएस की केंद्रीय कार्यकारिणी ने 5 मार्च से एसकेएम के चंडीगढ़ पक्का मोर्चा की पूर्व संध्या पर पंजाब के कई किसान नेताओं की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है।

पंजाब सरकार कई दौर की बातचीत का दावा कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी समस्या का समाधान निकालने में नाकाम रही है।

गिरफ्तारियाँ दिखाती हैं कि कृषि विपणन सुधारों के संबंध में AAP की वास्तविक स्थिति कॉरपोरेट समर्थक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की समर्थक है। 2020 में यह दिल्ली में 3 दिसंबर, 2020 को तत्कालीन मंडी अधिनियम के कार्यान्वयन को अधिसूचित करने वाली पहली राज्य सरकार थी।

चंडीगढ़ मोर्चा की योजना पंजाब सरकार को नई कृषि विपणन नीति का विरोध करने और किसानों के लिए अपने चुनावी वायदों को लागू करने के लिए किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की है।

पंजाब एसकेएम ने किसानों के कर्ज के एकमुश्त निपटान की मांग की है, हर खेत, हर घर तक पानी की व्यवस्था, राज्य सरकार 6 विशिष्ट राज्य फसलों – मक्का, बासमती, मूंग, आलू, फूलगोभी और मटर के लिए C2+50% पर एमएसपी सुनिश्चित करने, भूजल के औद्योगिक प्रदूषण को रोकना, गन्ना बकाया का भुगतान, और नजूल और गांव की सामान्य भूमि आदि पर कबिज किसानों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करना, आदि हैं।

जाहिर तौर पर आप सरकार किसानों की समस्याओं को हल करने में उदासीन है और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र में आरएसएस भाजपा सरकार के समर्थन में काम कर रही है।

एआईकेएमएस ने सरकार द्वारा दमन नहीं रोकने और नेताओं को रिहा नहीं करने की स्थिति में अखिल भारतीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

एआईकेएमएस ने अपनी सभी इकाइयों से कल, 5 मार्च, 2025 को होने वाले विरोध प्रदर्शन में इन गिरफ्तारियों की निंदा करने का आह्वान किया है।

चंडीगढ़ 4 मार्च 2025: इफ्टू से सम्बंधित यूनियन के झंडे तले अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करते पंजाव के निर्माण मजदूर

If Undelivered, Please Return to

Pratirodh Ka Swar

Monthly

Balmukand Khand,
Girinagar,
New Delhi-110019

Hindi Organ of CPI(ML)-New Democracy

R. N. 47287/87

Book Post

To

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली-110019 से मुद्रित तथा प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार